has not perceived any reluctance by these companies in pursuing their proposals on account of the sanctions announced recently by the US Government.

(b) Details of proposal received:

S.No.	Name of Company	Proposal
1.	Enron International, USA	For setting up gas fired power plants at 5-7 location totalling a capacity of 10000MW Specific location have not been indicated.
2.	Southern Electric, USA	For setting up coal based plant (6x660 MW) in the state of Orissa.
3.	China National Coal Mining Engineering equipment Group Corporation, China	For setting 1000 to 1500 MW project at Cuddalore, Tamil Nadu and coal based project at Tenughat, (capacity etc. not indicated).

(c) and (d) The modalities for setting up these projects are being finalised.

World Bank Assistance to NTPC

820. SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of POWER be pleased to state;

(a) whether in the wake of sanctions threat by USA over the recent underground nuclear tests conducted by Government, any chage in the World Bank assistance for the national Thermal Power Corporation is anticipated;

(b) if so, the details thereof;

(c) the likely impact on the power projects taken up by NTPC as a result thereof; and

(d) the manner in which Government propose to meet the financial gap in the event of withdrawal of assistance by the World Bank?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (d) National Thermal Power Corporation (NTPC) is presently implementing Vindhyachal Thermal Power Project Stage-II (1000 MW) and Kayamkulam Combined Cycle Power Project (350 MW) with World Bank funding. A first tranche time slice loan of US $ 400 million has already been committed by the World Bank which is effective from 1994. Out of this US $ 274.03 million has already been drawn and utilised by NTPC. NTPC should be in a position to draw the undisbursed portion of this loan, which is already committed. Further, discussions are on by NTPC with the World Bank for second tranche time slice loan for funding Talcher Thermal Power Project Stage-II and eligible expenditure for Vindhyachal. Thermal Power Project Stage-II and Kayamkulam Combined Cycle Power project beyond the closing date of the first tranche.

NTPC will arrange funds from the International/domestic markets, in the event of any difficulty in getting disbursement from the loan already committed or non-materialization of the second tranche time slice loan. There will be no adverse effect on the implementation of NTPC projects.

हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना

821. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिमला के निकट नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने से परियोजना के स्वरूप को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना में बांध की ऊंचाई कितनी होगी और अब तक परियोजना की निर्माण लागत अपनी मूल निर्माण लागत से कितनी अधिक आंकी जा चुकी है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ङ) जी हां, 4337.95 करोड़ की अनुमोदित लागत का

(मार्च 1993 का मूल्य स्तर) वाली नाथपा झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6 x 250 मे.वा. - 1500 मे. वा.) नाथपा झाकड़ी नाथवा झाकड़ी पावर कारपोरेशन (एनजेपीसी) के निर्माणाधीन है। अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बांध की ऊंचाई 60.5 मीटर है। उत्तरोतर भूस्खलन के कारण जलाशय की भण्डारण क्षमता सीमान्त रूप से घटी है। परियोजना के अनुमोदन के समय यथा परिकल्पित व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान लाभो समेत क्षतमा के अधिकतम समुपयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए एनजेपीसी ने बांध की ऊंचाई 7.0 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अब, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के जांचाधीन है। 4337.95 करोड़ रुपये (मार्च 1993 का मूल्यास्तर) की अनुमोदित लागत अनुमानो की तुलना में के.वि.प्रा. द्वारा मूल्यांकित की गई संशोधित समापन लागत 7217.05 करोड़ रुपये है।

टिहरी बांध का कार्य पूरा होना

822. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सन् 1962 में प्रारंभ हुई टिहरी बांध परियोजना एक सफेद हाथी सिद्ध हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के अनुमान बदलते रहते हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि जब से यह परियोजना केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से लेकर टी.एच.डी.सी. को सौंपी है तब से इसकी गुणवत्ता का ह्रास और धन की बर्बादी हुई है,

(घ) क्या यह भी सच है कि टी.एच.डी.सी. के पास उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के समान अनुभवी लोगों की भारी कमी है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार स्थिति में सुधार लाने और अंतिम रूप से निर्धारित समय सीमा में इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना को मूलत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के तौर पर निष्पादित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की लागत 1370.86 करोड़ रु० (1987 मे मूल्य स्तर पर) थी। वर्ष 1989 में इसके राज्य सरकार से टिहरी जल विद्युत विकास निगम को अंतरित किए जाने के पश्चात् 1000 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता के साथ जल विद्युत परियोजना चरण-2 और टिहरी बांध का अनुमोदन 2815 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर किया गया था। इस परियोजना की अतंतिम अनुमानित लागत दिसम्बर, 1997 के मूल्य स्तर पर 4570 करोड़ रुपये है। लागत में वृद्धि, सामान्य मूल्य बढ़ोत्तरी, पुनर्वास पैकेज पर व्यय और पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों के कारण से है। इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित की गई है क्योंकि उत्पादित ऊर्जा की लागत का परिकल्पन पुनर्वास पैकेज और पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों पर किए गए अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए 1.20 रुपये प्रति यूनिट किया गया है।

(ग) कार्य की गुणवत्ता अथवा निधियों के अपव्यय के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। कार्य की प्रगति इस परियोजना पर अब तक किए गए व्यय के अनुरूप रही है। काफर बांध की ऊंचाई बढ़ाकर पृथ्वी स्तर 661 कर दी गई है। भूमिगत विद्युत गृह के सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और खुदाई का 60% कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य बांध का कार्य आरंभ हो चुका है और बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। उत्पादन संयंत्र और उपस्कर के लिए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस प्रकार परियोजना संबंधी सभी प्रमुख गतिविधियों चल रही हैं।

टिहरी जल विद्युत विकास निगम के पास अनुभवी इंजीनियरों से सुसज्जित एक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग है। इसके अतिरिक्त निर्माण की गुणवत्ता जल विद्युत क्षेत्र स्वतंत्र विशेषज्ञों से सुसज्जित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा नियमित अंतरालों पर जांच और आवधिक निरीक्षण पर निर्भर करती है। परियोजना स्थल पर तैनात रूकी विशेषज्ञ भी निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। टिहरी जल विद्युत विकास निगम के पास उ.प्र. सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों से अनुभवी इंजीनियर नियमित सूची पर हैं। इस परियोजना को वर्ष 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

Power Projects in Nepal

823. **DR. JAGANNATH MISHRA:** Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether India and Nepal have signed any agreement in power sector in February, 1996;

(b) if so, the main features of the agreement;

(c) to what extent Government have agreed to help Nepal in the power sector;